



अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं का लाभ लाखों युवाओं को मिला है।

'उस्ताद', 'गरीब नवाज स्वरोजगार योजना', 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल' आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगारपरक कौशल विकास और रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियां शामिल हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित हजारों स्वास्थ्य सहायक कोरोना से प्रभावित लोगों की सेहत-सलामती की सेवा में लगे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायक, हॉस्पिटिलिटी असिस्टेंट, स्वदेशी सेनानी, टैक्स फैसिलिटेटर, कारपेंटर, टेलरिंग आदि के रोजगारपरक कौशल विकास के जरिये रोजगार-रोजगार के मौके मुहैया कराये जायेंगे।





अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
हेल्पलाइन नं. 1800-11-2001,
वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in



प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

पिछले लगभग 6 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत देश भर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आर्थिक-शैक्षिक-सामाजिक एवं रोजगारपरक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जिनमें शामिल हैं-

1512 नए स्कूल भवन, 22514 अतिरिक्त क्लास रूम, 630 हॉस्टल, 152 आवासीय विद्यालय, 8820 स्मार्ट क्लास रूम (केंद्रीय विद्यालयों सहित), 32 कॉलेज, 94 आईटीआई, 13 पॉलिटेक्निक, 2 नवोदय विद्यालय, 403 सद्भाव मंडप (बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र), 598 मार्किट शेड, 2842 स्कूलों में टॉयलेट एवं पेयजल सुविधाएँ, 135 कॉमन सर्विस सेंटर, 22 वर्किंग वीमेन हॉस्टल, 1717 विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं, 5 अस्पताल, 8 हुनर हब, 10 विभिन्न खेल सुविधाएँ, 5956 आंगनवाड़ी





अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
हेल्पलाइन नं. 1800-11-2001,
वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in



हुनर हाट

Hunar Haat

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों में आयोजित किये जा रहे “हुनर हाट”, हुनर के उस्ताद दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, खानसामों को मौका-मार्किट मुहैया कराने का प्रामाणिक प्लेटफार्म साबित हुए हैं।

पिछले लगभग 5 वर्षों में “हुनर हाट” के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराये गए हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आने वाले दिनों में देश के विभिन्न भागों में होने वाले “लोकल से ग्लोबल” संकल्प के साथ “हुनर हाट” के माध्यम से हस्तनिर्मित स्वदेशी सामानों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मौका-मार्किट मुहैया कराया जायेगा।





शैक्षिक सशक्तिकरण

पिछले लगभग 6 वर्षों में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों— जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख एवं मुस्लिम समुदाय— के छात्र-छात्राओं को प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स, बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृति आदि स्कॉलरशिप्स दी गई हैं।

लाभार्थियों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चियां शामिल हैं।

मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के प्रयासों का नतीजा है कि मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो पहले 72 प्रतिशत था अब घट कर 32 प्रतिशत रह गया है जिसे आने वाले दिनों में जीरो प्रतिशत करना हमारा लक्ष्य है।





अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
हेल्पलाइन नं. 1800-11-2001,
वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in



वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग

वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटाइजेशन और जियो टेगिंग/जीपीएस मैपिंग से वक्फ माफियाओं पर अंकुश लगाया वहीं दूसरी ओर वक्फ सम्पत्तियों का समाज के भलाई के लिए सदुपयोग सुनिश्चित किया। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, हासिप्टल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिंग की है।

- देश भर में लगभग 6 लाख 52 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियाँ हैं।
- सभी राज्य वक्फ बोर्डों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है।
- 95 प्रतिशत से ज्यादा वक्फ सम्पत्तियों का GIS/GPS मैपिंग का काम पूरा हो गया है।
- सभी 32 राज्य वक्फ बोर्डों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है।